IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 9, Issue 2, September 2021

क्षेत्रीयतावाद

(Regionalism)

डॉ. राधिका देवी
असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
ए. के. पी. (पी. जी.) कॉलिज, खुर्जा, जिला–बुलन्दषहर, उ. प्र.

''नेताओं और भारत से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पर्यवेक्षकों की आशंकाओं के बावजूद पुनर्गठन (भाषायी आधार पर राज्यों के पुर्नगठन) से भारत का राजनीतिक नक्शा अधिक सुसंगत हो गया और राष्ट्र की एकता को भी खास नुकसान नहीं पहुँचा। बल्कि इससे लाभ यह हुआ कि झगड़े का कारण दूर हुआ और राज्यों का कामकाज ऐसी भाषा में होना सम्भव हुआ, जिसे जनसाधारण समझ सकें। बल्कि बाद के अनुभव से तो यह कहा जा सकता है कि भाषा जोड़ने वाली शक्ति सिद्ध हुई। यदि इसमें कोई आशंका की बात है तो यही कि उपभाषाओं और स्थानीय संस्कृतियों के आधार पर राज्यों के टुकड़े न हो जाएं।''[1]

क्षेत्रीयतावाद का अर्थः

क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे–से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, आदि कारणों से अपने पृथक् अस्तित्व के लिए जागरूक है।

'क्षेत्र' शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी 'सांस्कृतिक समानता' है। किसी भौगोलिक प्रदेश को भी क्षेत्र के आधार पर सम्बोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास की भूमि से उनका भावात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तथा कालान्तर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से 'क्षेत्र' एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है।[2] किसी भी भू–भाग को क्षेत्र कहने के लिए कतिपय तत्वों का होना आवश्यक है, किन्तु आज तक उन तत्वों का ठीक तरह से निर्धारण नहीं हो सकता।[3] अनेक तत्वों जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति–रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन–सहन के तरीके, आदि की अन्तः क्रियाओं से किसी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। **प्रो. श्रीराम माहेश्वरी** का मत है कि क्षेत्र इनसे भी कुछ अधिक होता है, क्षेत्र के लोगों में साथ रहने की भावात्मक एकता होती है और दूसरोंसे अपने को पृथक् मानने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति वह सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका साफ मतलब है कि वह अपने को माराष्ट्रियन से थोड़ा भिन्न मानता है चाहे सभी महाराष्ट्रियन यह महसूस करते हों कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लोग भिन्न हैं। ऐसी भावनाएं सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं और उनसे कोई भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता।[4]

भारत में क्षेत्रीयवाद : ऐतिहासिक विरासत–

भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है अपितु वैचारिक परम्परा, धर्म और संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने भारत की इस सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया। स्वतन्त्रता की बेला पर भारत दो भागों में विभक्त था–ब्रिटिश भारत के प्रान्त एवं देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना तो जाग्रत हुई, किन्तु ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं किया अपितु अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर किया। देशी रियासतों में थोड़ी बहुत आन्तरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया। स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 9, Issue 2, September 2021

इस सन्दर्भ में प्रारम्भिक रूप से दो समस्याएं सामने आयीं–राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अन्तर्गत केन्द्र–राज्य सम्बन्धों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुर्नसीमांकन एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है।[5]

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण–

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं जो इस प्रकार है :–

- **भौगोलिक–**भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, आदि को यदि पृथक् राज्यों का दर्जा दिया जाएं तो भी वे केरल, नागालैण्ड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे।
- **सांस्कृतिक–** कुछ राज्यों में कई भाषाभाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते है।
- **ऐतिहासिक–** राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। वर्तमान समय में भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक् राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक सम्बन्धों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है।
- **आर्थिक कारण–** भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। इससे इन पिछड़े क्षेत्रों में असन्तोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। उदाहरणार्थ, राजस्थान में दक्षिण–पूर्वी राजस्थान, और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया और वे अपने लिए पृथक, राज्य की मांग करने लगे।
- **भाषा–** भारत में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक–दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गयीं।
- **जाति–** जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही वहां क्षेत्रीयतावाद की उग्र प्रवृत्ति दिखलायी देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति **प्रभावक तत्व** रहा है।
- **राजनीतिक कारण–** राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक् राज्य बन जायेगें तो उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दलों जैसे–डी. एम. के. और अकाली दल, आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्जवलित की है। वर्तमान समय की परिस्थितियों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रबल बनाने में इस राजनीतिक कारण की भूमिका बहुत बढ़ गई है।[6]

क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम–क्षेत्रीयतावाद की भावना जन–जीवन में जड़ पकड़ने के कारण वर्तमान समय में हमारा देश अनेक क्षेत्रों में बंट गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम निम्न प्रकार है :–

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 9, Issue 2, September 2021

- **विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव**–संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है, वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक यहां तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे यह चिन्ता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा।
- **राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के बीच सम्बन्धों को विकृत होना**– भारत में क्षेत्रीयता के कारण केन्द्रीय सरकार तथा राज्य के बीच का सम्बन्ध कभी–कभी अत्यन्त कटु रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े–बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने–अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केन्द्रीय सरकार जिसकी तरफ भी थोड़ा–सा झुक गयी वही विवाद का विषय बन जाता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता है।
- **स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास**– क्षेत्रीयता का एक और दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप अलग–अलग क्षेत्र में इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभारकर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति क रना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही राष्ट्रीय हितों का थोड़ा सा भी ख्याल रहता है, उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केन्द्रित हो जाता है।
- **भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना**–क्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने का कारण बनती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा सम्बन्ध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है जिसके कारण प्रादेशिक भाषा की आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उन क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नंहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है।[7]
- **राष्ट्रीय एकता को चुनौती**– संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर कुठाराघात करती हैं, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक् राज्य के प्रश्न को लेकर तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीयतावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ राजनीतिज्ञ **ज्योति वसु** कहते हैं : 'समय बीतने के साथ–साथ मैं भारतीयता को कमजोर होते हुए देख रहा हूँ।[8]

क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय–राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज नहीं है। इसे नियत्रित करना ही उचित है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों को सुझाया जा सकता है :

- केन्द्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप–सांस्कृतिक क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव हो जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो।
- सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 9, Issue 2, September 2021

- भाषा सम्बन्धी झगड़ों का समाधान शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस सम्बन्ध में सबसे उचित समाधान यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाएं।
- हिन्दी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए। अपितु इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें।
- प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाएं जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को अपना सके।
- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का सन्तुलित प्रतिनिधित्व हो जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खण्डन हो सके और केन्द्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी सन्देह न रहे।
- जहां तक सम्भव व व्यावहारिक हो उप–सांस्कृतिक क्षेत्रों को उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाएं, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा आचार–संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और ऐसे अवसर कभी जाएं कि उन्हें एक–दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। संकीर्ण मनोभाव वाले नेतागण इसी प्रकार के अवसरों की राह तकते रहते हैं और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकारों और विशेषकर केन्द्रीय सरकार के द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का मौका कभी नहीं दिया जाना चाहिए।

भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद को समाप्त कर पाना सम्भव नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां संयमित और नियन्त्रित रूप में रहें जिससे क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद में सामंजस्य की स्थिति सम्पूर्ण अंशों में बनी रहे।

संदर्भ सूची

[1]. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, पृ. 83–84।

[2]. A region is a profound sociological fact neglected in its being treated as the nucleus of social aggregation for multiple purpose. Dr. Shri Ram Maheshwari, State Governments in India (Macmillan 1979), P.185.

[3]. Ibid., p. 185.

[4]. Ibid., p. 186.

[5]. Dr. Pukhraj Jain, Indian Government Politics, P. 259.

[6]. Dr. Pukhraj Jain, Indian Government Politics, P. 259-260.

[7]. Dr. Pukhraj Jain, Indian Government Politics, P. 269.

[8]. "I find less and less Indianness, as the days go by". Jyoti Basu on Almati Dam Dispute (Quoted in The Times of India; 13 Dec, 96)

[9]. Rajni Kothari, Politics in India pp. 330-332